

Minister, it is proposed to withdraw the Essential Commodities (Amendment) Bill, 1998 pending in the Lok Sabha and introduce the revised Essential Commodities (Amendment) Bill, 1999 in the Lok Sabha.

(b) The proposed amendments include substantial increase in fines and imprisonment, making of all offences cognizable and non-bailable except the minor offences committed for the first time, requirement of prior permission of an officer not below the rank of Executive Magistrate for making entry, search and seizure, power of arrest to be exercised by an officer not below the rank of Sub-Inspector of police, sale of seized goods to be sold through PDS, provision for allowance of margin between physical stock and stock in record, appeal against confiscation to lie with the State Government and deletion of the item "component parts and accessories of automobiles" from the list of essential commodities.

(c) and (d) The amendments aim at providing more deterrent action against hoarders and blackmarketeers.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्नों के वितरण में घाघली

1135. श्री नरेन्द्र मोहन: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया गया खाद्यान्न लक्षित व्यक्तियों तक पहुंचता है;

(ख) क्या भारत सरकार इस संबंध में किसी प्रकार की घाघली की जानकारी रखती है; और

(ग) वे कौन-कौन से राज्य हैं, जहाँ से भारत सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कमियों या खामियों की जानकारी प्राप्त हुई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) जी, हाँ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न लक्षित उपभोक्ताओं को पहुंचते

हैं। किन्तु इन खाद्यान्नों के कुछ विपथन होने की संभावना से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। केन्द्रीय सरकार चावल, गेहूँ, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल जैसी कतिपय आवश्यक वस्तुओं की वसूली करती है और इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर राज्यों को उपलब्ध करती है और राज्य सरकारें उचित दर दुकानों के नेटवर्क के जरिये इन वस्तुओं को उपभोक्ताओं के बीच वितरित करती हैं।

गर्भपात के मामलों में बढ़ोतरी

1136. श्री दिलीप सिंह जुदेव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राहरी क्षेत्रों में गर्भपात करवाने के मामलों में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है तथा शिक्षित महिलाएं बालिका शिशु को जन्म देने में और उदासीन हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार बालिका जन्म धारण को सुरक्षित करने तथा उनके गर्भपात किए जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार ने देश में प्रतिवर्ष हो रहे गर्भपातों की सही संख्या का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एंजिलमलाई): (क) जी, हाँ। चिकित्सीय गर्भ-समापन (एम-टी-पी-ए) अधिनियम, 1971 के लागू होने के समय से वैध गर्भपातों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वैसे, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि शिक्षित महिलाएं लड़कियों को जन्म देने में उदासीन हो रही हैं।

(ख) चिकित्सीय गर्भ-समापन (एम-टी-पी-ए) अधिनियम, 1971 और नियम तथा विनियम, 1975 अवैध गर्भपातों को दृढ़ता से निरुत्साहित करते हैं जिन्हें के लिए दण्ड भी निर्धारित किया गया है। इस अधिनियम में ऐसी विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गई हैं जिन्हें तहत कतिपय परिस्थितियों में वैध गर्भपातों की अनुमति दी जा सकती है।

प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग-निवारण) अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन के माध्यम